Pariksha Saathi — दैनिक करंट अफेयर्स

12 अक्टूबर 2026 • हिंदी

SSC CGL • CHSL • MTS • IBPS PO/Clerk • SBI PO/Clerk • RRB — 26 खबरें + 5 प्रश्न • स्रोत: PIB (सभी खबरें आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों से)

1 भारत की BRICS अध्यक्षता में अहमदाबाद में हुए BRICS पारंपरिक और स्वदेशी प्रदर्शन खेल

Ahmedabad Hosts BRICS Traditional and Indigenous Demonstration Games Under India's 2026 Chairship

SSC • General

भारत की 2026 की BRICS अध्यक्षता के तहत 12 अक्टूबर को अहमदाबाद के नारणपुरा स्थित वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में BRICS पारंपरिक और स्वदेशी प्रदर्शन खेल आयोजित किए गए। एक दिन का यह आयोजन केंद्रीय खेल मंत्रालय ने गुजरात सरकार के साथ मिलकर किया, और इसे जान-बूझकर गैर-प्रतिस्पर्धी रखा गया: उद्देश्य पदक देना नहीं, बल्कि पारंपरिक खेलों का प्रदर्शन, दस्तावेज़ीकरण और आपसी आदान-प्रदान था। दस देशों ने अपनी-अपनी परंपराएं पेश कीं — भारत ने मलखंभ, योगासन और कलरीपयट्टू दिखाए; ब्राज़ील ने कैपोइरा और स्वदेशी लॉग रेस; चीन ने वुशु और लायन डांस; रूस ने सैम्बो और गोरोदकी; ईरान ने ज़ूरखाने; दक्षिण अफ्रीका ने क्गाटी; और बेलारूस, बोलीविया, कज़ाखस्तान तथा UAE ने भी भाग लिया। खेलों का उद्घाटन करते हुए खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने BRICS सहयोग के तीन सुझाव रखे: पारंपरिक और स्वदेशी खेलों का एक स्वैच्छिक BRICS संग्रह (रिपॉज़िटरी), खिलाड़ियों-प्रशिक्षकों-शोधकर्ताओं के बीच आदान-प्रदान, और आगे के BRICS खेल आयोजनों में ऐसे खेलों का समय-समय पर प्रदर्शन। उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने खेलो इंडिया पहल के लिए लगभग 3.76 अरब अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता की है। उद्घाटन में गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहे।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322256

2 सेना ने जवानों के लिए 'भारत राइस' शुरू किया, आपात सैन्य परिस्थितियों में FCI गोदामों के उपयोग के लिए MoU

Army Introduces 'Bharat Rice' for Troops, Signs MoU to Use FCI Warehouses in Operational Contingencies

SSC • General

12 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में भारतीय सेना ने सशस्त्र बलों के लिए बेहतर गुणवत्ता वाला 'भारत राइस' शुरू किया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी मौजूद थे। यह चावल रक्षा मानकों के अनुसार मिल किया जाएगा, वित्त वर्ष 2026-27 में NAFED के माध्यम से आपूर्ति होगा और सीधे सेना के सप्लाई डिपो तक — लद्दाख और पूर्वोत्तर के डिपो सहित — पहुंचाया जाएगा; अब डिपो को स्थानीय FCI केंद्रों से स्टॉक उठाने की ज़रूरत नहीं होगी। अग्रिम चौकियों पर ढुलाई आसान करने के लिए यह 10 किलो और 30 किलो के बैग में आएगा। जवानों से मिले फीडबैक के आधार पर यह पहल सेना के आपूर्ति एवं परिवहन महानिदेशालय ने आगे बढ़ाई, और इसमें सेना, FCI, NAFED और खाद्य विभाग के बीच लगभग 18 महीने का समन्वय लगा। इसी कार्यक्रम में सेना और भारतीय खाद्य निगम (FCI) के बीच एक MoU पर हस्ताक्षर हुए, जो पांच साल के लिए मान्य है और आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है। इसके तहत आपात सैन्य परिस्थितियों में सेना FCI के चिन्हित गोदामों, श्रमिकों और माल ढुलाई उपकरणों का उपयोग कर सकेगी। रक्षा मंत्री ने इस व्यवस्था को ऑपरेशन सिंदूर से मिले सबक से जोड़ा और कहा कि लॉजिस्टिक्स अपने आप में युद्ध-शक्ति है तथा भविष्य के संघर्ष बहुत कम चेतावनी के साथ आ सकते हैं।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322149

3 इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का नया मुख्यालय नई दिल्ली के 55 लोधी एस्टेट में

International Big Cat Alliance Moves Into New Headquarters at 55 Lodhi Estate, New Delhi

SSC • General

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 12 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के 55 लोधी एस्टेट में इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) के नए कार्यालय का उद्घाटन किया; अब यही गठबंधन के मुख्यालय का पता है। IBCA के महानिदेशक एस. पी. यादव ने अतिथियों को संगठन के काम की जानकारी दी। कार्यक्रम में भारत की पहल पर बने अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों — अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) और ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस — के प्रमुखों के साथ संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, विश्व बैंक, ADB, IUCN, WWF और FAO के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। IBCA भारत में मुख्यालय वाला, संधि पर आधारित एक अंतर-सरकारी संगठन है, जो सात बड़ी बिल्लियों — बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा — के संरक्षण के लिए काम करता है। मंत्रालय के अनुसार भारत समेत 29 देश अब इसके सदस्य हैं, 5 देशों ने पर्यवेक्षक का दर्जा चुना है और 11 और देशों ने सदस्य बनने की सहमति दी है। भारत ने 2023-24 से 2027-28 तक पांच वर्षों के लिए ₹150 करोड़ देने का वादा किया है। लगभग ढाई साल में गठबंधन ने विदेशी प्रतिभागियों के लिए ITEC के तहत दो क्षमता-निर्माण कार्यक्रम, 20 देशों के पशु चिकित्सकों के लिए बड़ी बिल्लियों के स्वास्थ्य पर एक कार्यक्रम चलाया है, और CITES व UNFCCC जैसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322416

4 ₹1 लाख करोड़ के RDI फंड ने पहले 19 सेकंड लेवल फंड मैनेजर चुने, ₹7,131 करोड़ की प्रतिबद्धता

₹1 Lakh Crore RDI Fund Names Its First 19 Second Level Fund Managers, Commits ₹7,131 Crore

Banking • SSC • General

निजी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (R&D) को पूंजी देने वाले सरकार के ₹1 लाख करोड़ के अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष (RDIF) ने 19 सेकंड लेवल फंड मैनेजर (SLFM) का पहला समूह चुन लिया है; यही बिचौलिया संस्थाएं वास्तव में पैसा निवेश करेंगी। इस चयन को सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (EGoS) ने 8 अक्टूबर 2026 को मंज़ूरी दी और 12 अक्टूबर को इसकी घोषणा हुई। इसमें 14 वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) और 5 फोकस्ड रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन (FRO) शामिल हैं, जिनके लिए RDIF ने कुल ₹7,131 करोड़ की प्रतिबद्धता की है। ये मैनेजर उन पात्र टेक्नोलॉजी उद्यमों में निवेश करेंगे जो टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल (TRL) 4 या उससे ऊपर की तकनीकों पर काम कर रहे हैं, और इनसे अपेक्षा है कि RDIF से मिली राशि के बराबर निजी पूंजी भी जुटाएं। कोष का संचालन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) के भीतर एक स्वतंत्र व्यावसायिक इकाई करती है। आवेदन जनवरी 2026 में मांगे गए थे, जिनकी जांच विशेषज्ञ समिति, ANRF की कार्यकारी परिषद और फिर EGoS ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह योजना नवंबर 2025 में शुरू की थी, ताकि उच्च-प्रभाव वाले अनुसंधान को लंबी अवधि की, जोखिम उठाने वाली पूंजी मिल सके। EGoS ने कोष के दायरे में पांच और तकनीकें भी जोड़ीं, और आगे फंड मैनेजरों के और समूह जोड़े जाएंगे।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322295

5 नड्डा ने हिमाचल के केलांग में ICMR के उच्च तुंगता चिकित्सा अनुसंधान केंद्र की आधारशिला रखी

Nadda Lays Foundation Stone of ICMR's High Altitude Medicine Research Centre at Keylong, Himachal Pradesh

SSC • General

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा ने 12 अक्टूबर 2026 को हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति ज़िले के केलांग में 'ICMR सेंटर फॉर हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च' की आधारशिला रखी। यह केंद्र उस फील्ड स्टेशन से विकसित होगा जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने करीब दस साल पहले केलांग में शुरू किया था, और इसे आधुनिक प्रयोगशालाओं वाला, पूरे साल काम करने वाला स्थायी संस्थान बनाने की योजना है। इसका काम यह समझने के लिए भारतीय वैज्ञानिक प्रमाण जुटाना होगा कि अधिक ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी, कड़ी ठंड और बदलती जलवायु स्वास्थ्य पर कैसे असर डालते हैं — जैसे ऊंचाई के अनुकूल होना (एक्लिमेटाइज़ेशन), मां और नवजात का स्वास्थ्य, बच्चों का विकास व पोषण, और हिमालयी समुदायों में बीमारियों का स्वरूप। इसकी खास बात सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (AFMS) के साथ साझेदारी है, ताकि शोध का लाभ बेहद ऊंचाई पर तैनात सैनिकों को भी मिले; AIIMS बिलासपुर इस क्षेत्र से आने वाले मरीज़ों पर पड़ने वाले असर का अध्ययन करेगा। केंद्र यह भी परखेगा कि ड्रोन, डिजिटल स्वास्थ्य साधन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दूरदराज़ इलाकों में स्वास्थ्य सेवा को कैसे बेहतर बना सकते हैं। कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, ICMR के महानिदेशक राजीव बहल और मंडी की सांसद कंगना रनौत भी मौजूद रहीं। इस शोध का लाभ हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को मिलने की उम्मीद है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322248

6 सीतारमण की सिंगापुर यात्रा संपन्न, भारत में दीर्घकालिक निवेश आकर्षित करने पर रहा ज़ोर

Sitharaman Wraps Up Singapore Visit Aimed at Drawing Long-Term Investment into India

Banking • General

वित्त मंत्रालय ने 12 अक्टूबर को बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8 से 11 अक्टूबर 2026 तक की चार दिन की आधिकारिक सिंगापुर यात्रा पूरी कर ली है। उन्होंने राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम और प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की, तथा उप प्रधानमंत्री गान किम योंग और विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन से भी मिलीं। बातचीत में चौथी भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक (ISMR) के नतीजों पर अमल और व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा हुई, और 2027 में सिंगापुर की ASEAN अध्यक्षता को ध्यान में रखकर आगे की चर्चा हुई। यात्रा का बड़ा हिस्सा निवेशकों से संवाद पर केंद्रित रहा: BlackRock, JPMorgan, PIMCO, Carlyle और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसी कंपनियों के साथ गोलमेज बैठक, और सिंगापुर के सॉवरेन निवेशकों GIC व Temasek के अलावा DBS, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, MUFG और Intel समेत कई संस्थाओं के साथ अलग-अलग बैठकें। उन्होंने राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) की सूची से चुनी गई अवसंरचना परियोजनाएं निवेशकों के सामने रखीं और गुजरात के GIFT IFSC के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया। सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण (MAS) के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों के टोकनाइज़ेशन, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) और आपस में जुड़ सकने वाली निपटान प्रणालियों पर चर्चा हुई, और सिंगापुर ने टोकनाइज़ेशन का अपना अनुभव साझा करने की पेशकश की। यात्रा में NIIF के CEO और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के अध्यक्ष भी साथ थे।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322491

7 PM गतिशक्ति के पांच साल: GIS आधारित मास्टर प्लान अब 58 केंद्रीय मंत्रालयों और सभी 36 राज्यों/UT में

PM GatiShakti at Five: GIS-Based Master Plan Now Spans 58 Central Ministries and All 36 States/UTs

SSC • Banking • General

13 अक्टूबर को PM गतिशक्ति के पांच साल पूरे होने से पहले, 12 अक्टूबर 2026 को PIB के एक पृष्ठभूमि नोट में बताया गया कि 13 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ राष्ट्रीय मास्टर प्लान (NMP) कैसे केवल बुनियादी ढांचे के नक्शे से आगे बढ़कर पूरी सरकार में इस्तेमाल होने वाली योजना प्रणाली बन गया है। यह योजना मंत्रालयों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के आंकड़ों को एक साझा GIS प्लेटफॉर्म पर लाती है, ताकि सड़क, रेल, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन और लॉजिस्टिक्स — यानी इसके 'सात इंजन' — की योजना एक साथ बनाई जा सके। अब इसमें 58 केंद्रीय मंत्रालय/विभाग और सभी 36 राज्य व केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं, और 23,493 से अधिक डेटा लेयर उपलब्ध हैं। प्रस्तावों की जांच तीन-स्तरीय व्यवस्था से होती है: कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाला सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह (EGoS), अवसंरचना मंत्रालयों का नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (NPG) और एक तकनीकी सहायता इकाई (TSU)। 11 अगस्त 2026 तक NPG करीब ₹18.66 लाख करोड़ की 396 परियोजनाओं की जांच कर चुका था। अक्टूबर 2025 से निजी क्षेत्र भी इस प्लेटफॉर्म पर 230 स्वीकृत, गैर-संवेदनशील डेटासेट देख सकता है। उदाहरणों में 699 किमी लंबा पुणे–बेंगलुरु एक्सप्रेसवे शामिल है, जिसके मार्ग में बदलाव से वन भूमि का उपयोग 19% कम हुआ, और लद्दाख–हरियाणा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर भी। 2022 में स्थापित गति शक्ति विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम के लिए 2.4 लाख से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दे चुका है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322164

8 PM-SETU: सूरत और विशाखापत्तनम के नौ सरकारी ITI का ₹440 करोड़ से उन्नयन करेगी AM/NS इंडिया

PM-SETU: AM/NS India to Upgrade Nine Government ITIs in Surat and Visakhapatnam Under ₹440 Crore Plan

SSC • General

कौशल विकास मंत्रालय ने 12 अक्टूबर 2026 को बताया कि सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) के दो क्लस्टर — गुजरात के सूरत में पांच और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में चार — इस्पात कंपनी आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (AM/NS इंडिया) को उद्योग साझेदार बनाकर आधुनिक बनाए जाएंगे। PM-SETU (प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs) योजना के तहत मंत्रालय के प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT), दोनों राज्य सरकारों और AM/NS इंडिया ने शेयरधारक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। हर क्लस्टर का संचालन एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) करेगा, जिसमें कंपनी की 51% और केंद्र व राज्य सरकार की 24.5%-24.5% हिस्सेदारी होगी। स्वीकृत निवेश लगभग ₹440 करोड़ है — सूरत के लिए ₹240 करोड़ और विशाखापत्तनम के लिए ₹200 करोड़ — जो योजना की पहली 14 निवेश योजनाओं (कुल ₹3,446 करोड़) में अब तक की सबसे बड़ी उद्योग प्रतिबद्धताओं में से एक है। योजना में आधुनिक वर्कशॉप, उद्योग की ज़रूरत वाले नए ट्रेड, संशोधित पाठ्यक्रम और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण शामिल है, और NAMTECH अकादमिक साझेदार होगा। PM-SETU का कुल परिव्यय ₹60,000 करोड़ है, और इसका लक्ष्य 1,000 सरकारी ITI का उन्नयन तथा पांच राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (NSTI) को मज़बूत करना है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322170

9 स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों/UT से कहा: अस्पताल और क्लिनिक अपनी सेवाओं की दरें साफ-साफ प्रदर्शित करें

Health Ministry Asks States and UTs to Make Hospitals and Clinics Display Their Service Rates Prominently

SSC • General

स्वास्थ्य मंत्रालय ने 12 अक्टूबर 2026 को बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि क्लिनिकल प्रतिष्ठान अपनी सेवाओं और सुविधाओं की दरें ऐसी जगह लगाएं जहां मरीज़ उन्हें आसानी से देख सकें। पत्र में क्लिनिकल प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 और क्लिनिकल प्रतिष्ठान (केंद्र सरकार) नियम, 2012 का हवाला दिया गया है। इन नियमों के तहत, जिन राज्यों/UT में यह अधिनियम लागू है, वहां हर क्लिनिकल प्रतिष्ठान को हर प्रकार की सेवा का शुल्क किसी प्रमुख स्थान पर स्थानीय भाषा और अंग्रेज़ी, दोनों में प्रदर्शित करना होता है। जहां यह अधिनियम नहीं अपनाया गया है, वहां अस्पताल राज्य/UT के अपने कानूनों के तहत आते हैं, जिनमें से कई में ऐसे ही प्रावधान हैं। मंत्रालय के अनुसार दरें सामने होने से परिवार इलाज का खर्च पहले से आंक सकेंगे, बिल से जुड़े विवाद घटेंगे और भरोसा बढ़ेगा। चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए इसे लागू कराने की ज़िम्मेदारी राज्यों/UT की है, जिनसे अनुपालन की समीक्षा करने और परामर्श जारी करने को कहा गया है। उनसे यह भी कहा गया है कि मेडिकल या आयुष वीज़ा पर भारत आने वाले विदेशी मरीज़ों के लिए पैकेज दरें प्रदर्शित करने को बढ़ावा दें।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322150

10 तटरक्षक बल के पर्वतारोहियों ने माउंट मुकुट फतह किया, 2027 में एवरेस्ट अभियान की अंतिम तैयारी

Coast Guard Mountaineers Summit Mount Mukut as Final Rehearsal for 2027 Everest Bid

SSC • General

भारतीय तटरक्षक बल (ICG) की 17 सदस्यीय पर्वतारोही टीम का 12 अक्टूबर 2026 को देहरादून में औपचारिक स्वागत हुआ, जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माउंट मुकुट पर सफल चढ़ाई के बाद टीम को फ्लैग-इन किया। तटरक्षक बल के अनुसार टीम 7 अक्टूबर 2026 को 7,045 मीटर ऊंची चोटी पर पहुंची; उसे हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट (HMI), दार्जिलिंग का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन मिला। अभियान 15 सितंबर को शुरू हुआ, 1 अक्टूबर को पहला बेस कैंप बना और खराब मौसम के बावजूद टीम शिखर तक पहुंची। यह 18 महीने के तैयारी कार्यक्रम का पांचवां और अंतिम चरण था, जिसका असली लक्ष्य 2027 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई है; यह अभियान ICG की स्वर्णिम जयंती (स्वर्ण जयंती) समारोहों के तहत प्रस्तावित है। बल का कहना है कि मुकुट से मिला अनुभव सीधे एवरेस्ट अभियान की योजना में काम आएगा। अपर महानिदेशक आनंद प्रकाश बडोला ने भी टीम को बधाई दी, जबकि मुख्यमंत्री ने कठिन हिमालयी इलाके में टीम की सहनशक्ति और तालमेल की सराहना की।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322315

11 TDB ने RDI फंड से बेंगलुरु की पेप्ट्रिस को AI से खोजी गई दवाओं के लिए ₹86 करोड़ की मदद दी

TDB Commits ₹86 Crore from RDI Fund to Bengaluru's Peptris for AI-Discovered Drug Candidates

Banking • SSC • General

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) ने 12 अक्टूबर 2026 को बताया कि उसने बेंगलुरु की कंपनी पेप्ट्रिस टेक्नोलॉजीज़ के साथ अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) फंड के तहत ₹86 करोड़ की सहायता का समझौता किया है। यह कंपनी नई दवाएं खोजने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती है। यह राशि ₹172 करोड़ की 'VIGOR' परियोजना के लिए है, जिसका लक्ष्य पेप्ट्रिस के AI प्लेटफॉर्म से खोजे गए चार दवा-उम्मीदवारों को तीन साल में प्रयोगशाला-स्तर की पुष्टि से आगे क्लिनिकल ट्रायल की तैयारी तक ले जाना है। ये दवाएं न्यूरोमस्कुलर विकारों व कैंसर, एलोपेसिया (बाल झड़ना), न्यूरोपैथी और ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (DMD) के लिए हैं। तकनीकी भाषा में, परियोजना हर अणु को टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल (TRL) 4 से TRL 6 तक ले जाना चाहती है — प्री-क्लिनिकल अध्ययन, फॉर्मूलेशन और नई दवा के परीक्षण-आवेदन (IND) से पहले ज़रूरी अध्ययनों के ज़रिए, नियामकीय मंज़ूरियों के अधीन। TDB की यह सहायता अनुदान नहीं, बल्कि वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ऋण (Optionally Convertible Debt) के रूप में है। TDB सचिव राजेश कुमार पाठक ने कहा कि AI दवा खोज का तरीका बदल सकता है, लेकिन कंप्यूटर के अनुमानों को असली इलाज में बदलने के लिए लगातार निवेश और कड़े परीक्षण चाहिए, और RDI फंड यही कमी पूरी करने के लिए है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322077

12 ग्रामीण विकास मंत्रालय और नेशनल एकेडमी ऑफ RUDSETI के बीच MoU; इस साल RSETI में 6.35 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण

Rural Development Ministry Signs MoU with National Academy of RUDSETI; RSETIs to Train 6.35 Lakh Rural Youth This Year

Banking • SSC • General

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 12 अक्टूबर 2026 को नेशनल एकेडमी ऑफ RUDSETI (NAR) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) का आदान-प्रदान किया, ताकि देशभर के ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थानों (RSETI) में एक समान मानक, बेहतर प्रशासन और मज़बूत क्षमता निर्माण सुनिश्चित हो सके। MoU का आदान-प्रदान ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल की मौजूदगी में हुआ। इसके तहत उम्मीदवारों का पंजीकरण 'कौशल पंजी' पोर्टल से होगा और उपस्थिति के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन होगा; RSETI राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के अनुरूप नए कोर्स चलाएंगे, उद्योग-स्तर के प्रशिक्षण उपकरण अपनाएंगे और मंत्रालय द्वारा अधिसूचित उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) के मुख्य कोर्स चलाएंगे। प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षुओं व प्रशिक्षकों का मूल्यांकन और प्रमाणन मंत्रालय के एकीकृत कौशल पोर्टल के ज़रिए मज़बूत किया जाएगा। इस वर्ष RSETI को 6.35 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य दिया गया है, जो पिछले साल के लक्ष्य से अधिक है; इसमें महिलाओं, SC/ST, दिव्यांगजनों और अन्य कमज़ोर वर्गों पर ध्यान रहेगा। मंत्रालय के अनुसार उद्देश्य यह है कि ग्रामीण युवा प्रशिक्षण के बाद टिकाऊ उद्यम शुरू कर सकें, जिसमें बसावट (settlement) और बैंक ऋण से जुड़ाव पर भी ध्यान दिया जाएगा।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322563

13 राष्ट्रीय सरस मेला पहली बार दिल्ली-NCR से बाहर: 13 से 31 अक्टूबर तक विजयवाड़ा में

National SARAS Mela Moves Outside Delhi-NCR for the First Time: Vijayawada to Host It from 13 to 31 October

SSC • Banking • General

ग्रामीण विकास मंत्रालय का राष्ट्रीय सरस मेला, जो महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) के उत्पादों का प्रमुख मंच है, पहली बार दिल्ली-NCR से बाहर आयोजित हो रहा है। मंत्रालय ने 12 अक्टूबर 2026 को बताया कि 2026 का संस्करण 13 से 31 अक्टूबर तक आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पुन्नमी घाट पर लगेगा, जिसे राज्य की 'सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी' (SERP) के साथ मिलकर आयोजित किया जा रहा है। इसमें 30 से अधिक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के SHG से जुड़ी 1,500 से ज़्यादा महिलाएं हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पाद और क्षेत्रीय व्यंजन लेकर आएंगी, साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 15 अक्टूबर को मेले का उद्घाटन करेंगी; इस मौके पर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस. अब्दुल नज़ीर, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के शामिल होने का कार्यक्रम है। यह मेला दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) और 2029 तक 6 करोड़ 'लखपति दीदी' बनाने के लक्ष्य से जुड़ा है; इसमें लखपति दीदी पवेलियन, 'SHAKTI' नाम की 16 फुट ऊंची कलाकृति और eSARAS ऑनलाइन बाज़ार से जुड़ाव होगा। NABARD और NIRDPR इसके सहयोगी साझेदारों में हैं।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322458

14 ARIES के नेतृत्व वाले अध्ययन ने सूर्य के ध्रुवों की माइक्रोवेव चमक को ध्रुवीय चुंबकीय क्षेत्र और कोरोनल होल से जोड़ा

ARIES-Led Study Links the Sun's Bright Microwave Poles to Its Polar Magnetic Field and Coronal Holes

SSC • General

कुछ खास माइक्रोवेव और रेडियो आवृत्तियों पर देखने पर सूर्य के ध्रुवीय क्षेत्र बाकी सतह से ज़्यादा चमकीले दिखते हैं; इसे 'माइक्रोवेव पोलर ब्राइटनिंग' कहते हैं, और इसका कारण अब तक स्पष्ट नहीं था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) ने 12 अक्टूबर 2026 को बताया कि भारतीय शोधकर्ताओं की एक टीम ने इसे बड़े और छोटे, दोनों पैमानों की चुंबकीय गतिविधि से जोड़ा है। यह अध्ययन DST के अधीन स्वायत्त संस्थान आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (ARIES), नैनीताल; भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (PRL) की उदयपुर सौर वेधशाला; IIT दिल्ली और IIT रुड़की ने मिलकर किया। जापान के नोबेयामा रेडियोहेलियोग्राफ के लगभग तीस साल के 17 GHz आंकड़ों को NASA की सोलर डायनेमिक्स ऑब्ज़र्वेटरी की तस्वीरों और विल्कॉक्स सोलर ऑब्ज़र्वेटरी के चुंबकीय मापों के साथ मिलाकर टीम ने पाया कि ध्रुवीय चमक ध्रुवीय कोरोनल होल के आकार के साथ और उससे भी अधिक सूर्य के ध्रुवीय चुंबकीय क्षेत्र की ताकत के साथ घटती-बढ़ती है। अलग-अलग चमकीले धब्बे अक्सर कोरोनल ब्राइट पॉइंट्स और कोरोनल जेट्स से मेल खाते थे। शोधकर्ताओं ने लंबे समय के व्यवहार में उत्तर और दक्षिण ध्रुव के बीच अंतर भी दर्ज किया। 'द एस्ट्रोफिज़िकल जर्नल' में प्रकाशित ये नतीजे सूर्य के ध्रुवीय वातावरण की स्थितियों और सौर पवन (solar wind) की उत्पत्ति को समझने में मदद करेंगे।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322253

15 छह राज्यों में नए राज्यपाल: आर्लेकर तमिलनाडु और ओ.पी. माथुर केरलम भेजे गए

Six Governors Appointed: Arlekar Shifted to Tamil Nadu, O.P. Mathur to Keralam

SSC • Banking • General

राष्ट्रपति भवन ने 12 अक्टूबर 2026 की देर शाम जारी एक विज्ञप्ति में छह राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की घोषणा की। इनमें से दो मौजूदा राज्यपालों के तबादले हैं: सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम (केरल) जाएंगे, जबकि केरलम में तैनात राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु की ज़िम्मेदारी दी गई है। बाकी चार नियुक्तियाँ इस प्रकार हैं: ओडिशा में ब्रज मोहन राम, कर्नाटक में डॉ. सुधा यादव, उत्तराखंड में डॉ. ढाल सिंह बिसेन और सिक्किम में दुष्यंत गौतम, जो माथुर के जाने से खाली हो रहा पद संभालेंगे। विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी बदलाव तुरंत लागू नहीं होगा; हर नियुक्ति उसी दिन से प्रभावी होगी जिस दिन संबंधित व्यक्ति नए राजभवन का कार्यभार ग्रहण करेगा। अभ्यर्थी अपनी राज्यवार राज्यपाल सूची अपडेट कर लें, क्योंकि राज्य और राज्यपाल का सही मिलान सामान्य ज्ञान में अक्सर पूछा जाता है। दो तबादलों को बाकी चार नियुक्तियों से अलग करके याद रखना उपयोगी रहेगा।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322578

16 सितंबर 2026 में खुदरा महंगाई बढ़कर 5.54%, खाद्य कीमतों ने बढ़ाया दबाव

Retail Inflation Rises to 5.54% in September 2026 as Food Prices Climb

Banking • SSC • General

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) द्वारा 12 अक्टूबर को जारी अनंतिम आँकड़ों के अनुसार सितंबर 2026 में देश की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.54% हो गई। यह आँकड़ा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) की नई श्रृंखला पर आधारित है, जिसका आधार वर्ष 2024 है, और यह अगस्त के अंतिम आँकड़े 4.83% से साफ तौर पर अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में कीमतें (6.08%) शहरी क्षेत्रों (4.88%) की तुलना में तेज़ी से बढ़ीं। सबसे ज़्यादा दबाव खाद्य वस्तुओं से आया: उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक पर आधारित खाद्य महंगाई एक महीने पहले के 5.97% से उछलकर 7.74% पर पहुँच गई। प्याज़ सबसे आगे रहा, जिसकी कीमत एक साल में दोगुने से भी ज़्यादा (108.09%) बढ़ी, जबकि चांदी के आभूषण, अदरक, लहसुन और नींबू भी सबसे तेज़ वार्षिक बढ़ोतरी वाली वस्तुओं में रहे। दूसरी ओर आलू और टमाटर अब भी पिछले साल से सस्ते रहे। कीमतों के आँकड़े 1,407 शहरी बाज़ारों और 1,465 गाँवों से जुटाए गए। अक्टूबर 2026 का CPI 12 नवंबर 2026 को जारी होगा।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322244

17 एशियाई खेल 2026: भारत के 85 पदकों में 27 सशस्त्र बलों के खिलाड़ियों ने दिलाए

Services Athletes' Best-Ever Asian Games: 27 of India's 85 Medals Came from the Armed Forces

SSC • Banking • General

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में उन सैन्य खिलाड़ियों को सम्मानित किया जिन्होंने हाल ही में जापान में हुए एशियाई खेलों में रिकॉर्ड प्रदर्शन किया। 19 खेल स्पर्धाओं में उतरे 92 सदस्यीय सर्विसेज़ दल ने 27 पदक (6 स्वर्ण, 11 रजत, 10 कांस्य) जीते, जो इन खेलों में सर्विसेज़ का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। पूरी भारतीय टीम 85 पदकों (21 स्वर्ण, 27 रजत, 37 कांस्य) के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर रही, यानी देश के कुल पदकों में लगभग एक-तिहाई हिस्सा अकेले सर्विसेज़ का रहा। कई उपलब्धियाँ भारत के लिए पहली बार दर्ज हुईं। नायब सूबेदार नीरू ढांडा ने दो स्वर्ण और एक रजत जीता और व्यक्तिगत महिला ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। नायब सूबेदार गुलवीर सिंह दो रजत और एक कांस्य के साथ एक ही एशियाई खेलों में तीन व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष ट्रैक-एंड-फ़ील्ड एथलीट बने। हवलदार सावन बरवाल ने 2:11:37 के राष्ट्रीय रिकॉर्ड समय के साथ मैराथन में रजत जीतकर इस स्पर्धा में भारत का 44 साल का इंतज़ार खत्म किया, और नायब सूबेदार सर्वेश कुशारे ने 56 साल बाद पुरुष ऊँची कूद में भारत को पदक दिलाया। रक्षा मंत्री ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों से 2028 के लॉस एंजेलिस ओलंपिक के लिए और ऊँचे लक्ष्य रखने को कहा।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322172

18 NHRC का 33वाँ स्थापना दिवस: CJI सूर्यकांत ने आयोग को मार्गदर्शक बताया, जल के अधिकार पर ज़ोर

NHRC Turns 33: CJI Surya Kant Calls the Commission a Guiding Light, Right to Water in Focus

SSC • General

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने 12 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अपने 33 वर्ष पूरे होने का समारोह मनाया, जिसके साथ जल के अधिकार पर 'Water as the Elixir of Life: Advancing Human Dignity through the Right to Water' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इस आम आलोचना का जवाब दिया कि आयोग केवल सिफ़ारिश कर सकता है; उन्होंने आयोग की तुलना एक प्रकाश स्तंभ से की, जिसका काम अन्याय को बलपूर्वक रोकना नहीं बल्कि अंधेरे में भटके लोगों को राह दिखाना है। उन्होंने कहा कि राज्य मानव अधिकार आयोगों की ज़िम्मेदारी खास है, क्योंकि वे उन जगहों के ज़्यादा करीब हैं जहाँ उल्लंघन होते हैं, और जल नीति की असली कसौटी यह है कि पानी सुरक्षित, भरोसेमंद हो और परिवार को ज़रूरत के समय उपलब्ध हो। NHRC के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और डिजिटल दुनिया, जहाँ गैर-सरकारी तत्वों का प्रभाव बहुत बढ़ गया है, नई चुनौतियाँ खड़ी कर रहे हैं, इसलिए दुनिया भर की मानव अधिकार संस्थाओं को खुद को नए सिरे से ढालना होगा। CJI ने आयोग के नए मोबाइल ऐप और रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की भी सराहना की।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322423

19 माहे श्रेणी का तीसरा पनडुब्बी-रोधी उथले जल पोत INS मंगरोल नौसेना में शामिल

INS Mangrol, Third Mahe-Class Anti-Submarine Shallow Water Craft, Joins the Navy

SSC • General

भारतीय नौसेना ने 12 अक्टूबर 2026 को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में INS मंगरोल (पेनेंट संख्या P82) को कमीशन कर अपने बेड़े में शामिल किया। यह पनडुब्बी-रोधी युद्धक उथले जल पोत (ASW-SWC) की माहे श्रेणी का तीसरा जहाज़ है, जिसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि ने देश में ही डिज़ाइन और तैयार किया है; इसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। समारोह की अध्यक्षता पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल संजय वत्सायन ने की। यह जहाज़ तट के पास के अभियानों के लिए बना है: पनडुब्बियों की खोज, पानी के नीचे निगरानी, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान और बारूदी सुरंग युद्ध से जुड़े काम। इसके सोनार, सेंसर और हथियार तटीय जल में पानी के नीचे के खतरों का पता लगाने और उन पर नज़र रखने में मदद करते हैं। वॉटरजेट इकाइयों को चलाने वाले तीन डीज़ल इंजन इसे उथले और संकरे समुद्र में तेज़ी से मुड़ने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता देते हैं। जहाज़ का नाम गुजरात के जूनागढ़ ज़िले के मछली बंदरगाह वाले कस्बे मंगरोल पर रखा गया है, और यह पुराने माइनस्वीपर INS मंगरोल (M85) की विरासत को आगे बढ़ाता है, जो अप्रैल 2004 तक नौसेना में सेवारत रहा।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322494

20 व्यापार समझौता लागू होने के बाद पहली भारत-ब्रिटेन JETCO बैठक, 2030 तक व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य

First India-UK JETCO Since Trade Pact Took Effect Sets Goal of Doubling Trade by 2030

Banking • SSC • General

भारत और ब्रिटेन की संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति (JETCO) का 16वाँ सत्र 12 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में हुआ, जिसकी अगुवाई वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट जोनाथन रेनॉल्ड्स ने की। भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) 15 जुलाई 2026 को लागू होने के बाद यह पहली JETCO बैठक थी, इसलिए चर्चा का बड़ा हिस्सा इस पर रहा कि कारोबारी इस समझौते का वास्तव में कितना लाभ उठा रहे हैं। दोनों पक्षों ने CETA के उपयोग की संयुक्त समीक्षा की और इसके तहत उप-समितियों व कार्य समूहों के गठन का स्वागत किया। बिज़नेस प्लेनरी में गोयल ने कंपनियों से 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखने और भारत-ब्रिटेन विज़न 2035 को व्यापक सहयोग का ढाँचा बनाने का आग्रह किया। उन्होंने सहयोग के पाँच प्राथमिक क्षेत्र गिनाए: बुनियादी ढाँचा और स्वच्छ ऊर्जा; उन्नत विनिर्माण और मज़बूत आपूर्ति श्रृंखला; तकनीक और नवाचार; वित्तीय सेवाएँ, जिनमें सिटी ऑफ़ लंदन और गिफ्ट सिटी के बीच बेहतर तालमेल शामिल है; तथा स्वास्थ्य सेवा और उपभोक्ता वस्तुएँ। उन्होंने यह भी कहा कि छोटे निर्यातकों की सुविधा के लिए टैरिफ अनुसूचियाँ और उत्पत्ति के नियम (रूल्स ऑफ़ ओरिजिन) सरल भाषा में, क्षेत्रीय भाषाओं सहित, समझाए जाएँ।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322389

21 IMD ने चक्रवात और समुद्री मौसम के लिए इंटरैक्टिव निर्णय सहायता प्रणाली जनता के लिए शुरू की

IMD Opens Interactive Cyclone and Marine Weather Decision Support System to the Public

SSC • General

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 12 अक्टूबर 2026 को चक्रवात चेतावनी और समुद्री मौसम सेवाओं के लिए एक सार्वजनिक निर्णय सहायता प्रणाली (DSS) शुरू की। वेबजीआईएस पर आधारित यह इंटरैक्टिव प्लेटफ़ॉर्म चक्रवात और समुद्री मौसम की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध कराता है। इसके नक्शों पर तूफ़ान का वास्तविक और अनुमानित मार्ग व तीव्रता, अनिश्चितता का दायरा (कोन ऑफ़ अनसर्टेन्टी), हवा का वितरण, ज़िलेवार वर्षा चेतावनी, तूफ़ानी लहरें (स्टॉर्म सर्ज) और नदी जलग्रहण क्षेत्रों के लिए वर्षा पूर्वानुमान देखे जा सकते हैं। यह आपदा प्रबंधकों, सरकारी एजेंसियों और आम नागरिकों के लिए है और IMD तथा क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र (RSMC), नई दिल्ली की वेबसाइट से उपलब्ध है। इसकी शुरुआत IMD की साल में दो बार होने वाली प्री-साइक्लोन एक्सरसाइज़ बैठक में हुई, जो 2008 से आयोजित हो रही है; इस बार बैठक अक्टूबर-दिसंबर के मानसून-पश्चात मौसम की तैयारी के लिए थी। इसकी अध्यक्षता मौसम विज्ञान के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्र ने की, जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के तीसरे उपाध्यक्ष भी हैं। NDMA, NDRF, सशस्त्र बलों, तटरक्षक बल और तटीय राज्यों सहित 30 से अधिक संगठनों के लगभग 230 प्रतिभागी शामिल हुए। तारीख का खास महत्व था: IMD द्वारा सटीक पूर्वानुमानित चक्रवात फैलिन (2013) और हुदहुद (2014) दोनों ने 12 अक्टूबर को ही तट पार किया था।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322562

22 पीएम धन-धान्य कृषि योजना का एक साल: गया, नागौर और उमरिया सर्वश्रेष्ठ ज़िले घोषित

PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana at One Year: Gaya, Nagaur and Umaria Ranked Best Districts

SSC • Banking • General

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) ने 11 अक्टूबर 2026 को अपना पहला साल पूरा किया, और कृषि मंत्रालय ने 12 अक्टूबर को नई दिल्ली के पूसा स्थित NASC में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर इसे चिह्नित किया। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में हुई थी और इसे 11 अक्टूबर 2025 को उन 100 ज़िलों के लिए शुरू किया गया था जो कृषि उत्पादकता, फसल सघनता और कृषि ऋण की उपलब्धता में पीछे हैं। यह अभिसरण (convergence) के ज़रिए काम करती है और 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं को, संबंधित राज्य योजनाओं के साथ, ज़िलेवार कार्ययोजनाओं के तहत एक साथ लाती है, और एक डैशबोर्ड पर 121 संकेतकों के आधार पर हर महीने ज़िलों की रैंकिंग करती है। समग्र रैंकिंग में गया (बिहार) पहले, नागौर (राजस्थान) दूसरे और उमरिया (मध्य प्रदेश) तीसरे स्थान पर रहा, जबकि योजना के छह उद्देश्यों पर अच्छे काम के लिए 18 अन्य ज़िलों को भी सम्मानित किया गया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पहले साल में नींव रखी गई है और दूसरे साल में किसानों के लिए दिखने वाले और मापे जा सकने वाले नतीजे आने चाहिए। उन्होंने राज्यों से 22 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक प्रस्तावित 'खेत बचाओ अभियान' में भाग लेने को भी कहा, जिसका उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित उपयोग बढ़ाना है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322267

23 भारत-ब्राज़ील-दक्षिण अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास IBSAMAR के नौवें संस्करण के लिए INS तरकश दक्षिण अफ्रीका रवाना

INS Tarkash Heads to South Africa for Ninth India-Brazil-South Africa Naval Exercise IBSAMAR

SSC • General

रक्षा मंत्रालय ने 12 अक्टूबर 2026 को बताया कि भारतीय नौसेना का गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट INS तरकश भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास के नौवें संस्करण IBSAMAR IX में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में तैनात है। IBSAMAR, IBSA ढाँचे के तहत 2008 से हर दो साल में आयोजित होता है, और इस बार का विषय 'Stronger Together Towards a Shared Future in the Maritime Domain' है। अभ्यास में सतह युद्ध, वायु-रोधी और पनडुब्बी-रोधी युद्ध, नौसैनिक हवाई अभियान, समुद्री अवरोधन, जहाज़ पर चढ़कर तलाशी और ज़ब्ती (VBSS), समुद्री डकैती-रोधी अभियान, खोज और बचाव, तथा क्षति नियंत्रण और अग्निशमन शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका की ओर से SAS अमाटोला, SAS किंग सेखुखुने I और SAS एडम कोक III जहाज़ तथा पनडुब्बी SAS मंथातिसी हिस्सा ले रहे हैं। ब्राज़ील ने लिंक्स हेलिकॉप्टर के साथ BNS बैरोसो भेजा है, जबकि INS तरकश पर एक चेतक हेलिकॉप्टर तैनात है। परीक्षा के लिए याद रखें: IBSAMAR एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तीन IBSA लोकतंत्रों, भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका, का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322377

24 TRAI की अप्रैल-जून 2026 रिपोर्ट: टेली-घनत्व 94.31%, प्रति उपयोगकर्ता मासिक मोबाइल डेटा खपत 28.39 GB

TRAI April-June 2026 Report: Tele-Density Reaches 94.31%, Mobile Data Use Hits 28.39 GB a Month

Banking • SSC • General

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 12 अक्टूबर को अप्रैल-जून 2026 तिमाही की 'भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट' जारी की। देश में कुल टेलीफ़ोन ग्राहकों की संख्या मार्च के अंत के 1,330.58 मिलियन से बढ़कर जून 2026 के अंत में 1,348.08 मिलियन हो गई, यानी तिमाही में 1.31% की बढ़त, और कुल टेली-घनत्व 93.26% से सुधरकर 94.31% हो गया। शहरी टेली-घनत्व 153.43% रहा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 60.89% था; कुल कनेक्शनों में ग्रामीण ग्राहकों की हिस्सेदारी 41.24% रही। इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 1,114 मिलियन से ऊपर पहुँच गई, जिनमें 1,087.50 मिलियन ब्रॉडबैंड पर हैं। डेटा की खपत लगातार बढ़ रही है: एक औसत मोबाइल डेटा उपयोगकर्ता ने हर महीने 28.39 GB डेटा इस्तेमाल किया, जो पिछली तिमाही में 26.70 GB था, जबकि वायरलेस डेटा के प्रति GB औसत राजस्व ₹7.51 से घटकर ₹7.13 रह गया। वायरलेस सेवा का प्रति उपयोगकर्ता औसत मासिक राजस्व (ARPU) 1.19% बढ़कर ₹187.12 हो गया। तिमाही में दूरसंचार क्षेत्र का समायोजित सकल राजस्व (AGR) ₹88,796 करोड़ रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही से लगभग 9.19% अधिक है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322388

25 भारत 13 अक्टूबर को नई दिल्ली में BIMSTEC गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेज़बानी करेगा

India to Host the First-Ever BIMSTEC Home Ministers' Meeting in New Delhi on 13 October

SSC • General

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 12 अक्टूबर 2026 को बताया कि भारत 13 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में BIMSTEC के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेज़बानी करेगा, और उन्होंने आने वाले मंत्रियों और सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत किया। X पर अपनी पोस्ट में, जिसे गृह मंत्रालय ने अपनी विज्ञप्ति में शामिल किया, उन्होंने इस बैठक को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध, नशीले पदार्थों, कट्टरपंथ, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह और साइबर खतरों से मिलकर लड़ने के साझा संकल्प को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि बेहतर तालमेल के ज़रिए सदस्य देश BIMSTEC क्षेत्र को अधिक सुरक्षित बनाना चाहते हैं। BIMSTEC (बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल) के सात सदस्य हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, और सुरक्षा इसके सहयोग के मान्य क्षेत्रों में से एक है। चूँकि यह समूह के गृह मंत्रियों की पहली बैठक है, इसलिए अभ्यर्थी इसे क्षेत्रीय समूहों और आंतरिक सुरक्षा सहयोग, दोनों विषयों के तहत नोट करें, और बैठक के बाद जारी होने वाले किसी संयुक्त वक्तव्य या परिणाम दस्तावेज़ पर भी नज़र रखें।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322415

26 दिल्ली में भारत-ब्रिटेन विज्ञान और नवाचार परिषद की 8वीं बैठक; जीनोमिक्स उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन

8th India-UK Science and Innovation Council Meets in Delhi; Genomics Centre of Excellence Opened

SSC • General

भारत और ब्रिटेन की विज्ञान और नवाचार परिषद (SIC) की आठवीं बैठक 12 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में हुई, जिसकी अगुवाई विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट जोनाथन रेनॉल्ड्स ने की; रेनॉल्ड्स उसी दिन भारत-ब्रिटेन व्यापार समिति की वार्ता के लिए भी राजधानी में थे। परिषद ने संयुक्त अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा की और इस पर चर्चा की कि प्रयोगशाला के काम को उपयोगी तकनीकों और उत्पादों में कैसे बदला जाए। दोनों मंत्रियों ने BRIC-CDFD-ONT इंडिया जीनोमिक्स सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस का उद्घाटन भी किया, जिसका नाम सेंटर फ़ॉर DNA फ़िंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स (जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद, BRIC का हिस्सा) और ब्रिटिश कंपनी ऑक्सफ़ोर्ड नैनोपोर टेक्नोलॉजीज़ के सहयोग को दर्शाता है। भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और इनोवेट UK के संयुक्त कार्यक्रम के तहत उन्नत विनिर्माण, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और नेट-ज़ीरो तकनीकों जैसे क्षेत्रों में आठ औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ स्वीकृत हुई हैं, जो कार्यान्वयन के अलग-अलग चरणों में हैं। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, जैव प्रौद्योगिकी और दूरसंचार को प्राथमिक क्षेत्रों में गिना गया, और यह सहयोग प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल (TSI) तथा भारत-ब्रिटेन विज़न 2035 पर आधारित है।

स्रोत: PIB — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322306

आज का अभ्यास — 5 प्रश्न

प्र.1 भारतीय रेलवे का 'विशेष अभियान 6.0', जो सितंबर-अक्टूबर 2026 में चल रहा है, किन दो विषयों पर केंद्रित है?

(A) डिजिटलीकरण और साइबर सुरक्षा
(B) स्वच्छता और लंबित मामलों में कमी
(C) ट्रैक विद्युतीकरण और सुरक्षा ऑडिट
(D) माल गलियारा विस्तार और स्टेशन पुनर्विकास

प्र.2 एक सप्ताह तक चलने वाला तटीय-सफाई अभियान SSSS 5.0, 2026 में किस अवसर पर संपन्न हुआ?

(A) विश्व महासागर दिवस
(B) विश्व पर्यावरण दिवस
(C) अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस
(D) राष्ट्रीय समुद्री दिवस

प्र.3 दूरसंचार विभाग (DoT) की सितंबर 2026 की सलाह के अनुसार, फर्जी सिम जारी करने और IMEI से छेड़छाड़ पर किस अधिनियम के तहत 3 वर्ष तक की कैद और ₹50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है?

(A) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
(B) भारतीय तार अधिनियम, 1885
(C) दूरसंचार अधिनियम, 2023
(D) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002

प्र.4 सितंबर 2026 में राष्ट्रपति ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 न्यायिक अधिकारियों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की?

(A) अनुच्छेद 124
(B) अनुच्छेद 217
(C) अनुच्छेद 226
(D) अनुच्छेद 233

प्र.5 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उद्घाटित एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) प्रमुखों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन किस संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है?

(A) राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)
(B) नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)
(C) केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
(D) पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो

उत्तर: 1-(B) 2-(C) 3-(C) 4-(B) 5-(B)

रोज़ का PDF: parikshasaathi.com/daily-pdf — सभी संस्करण: parikshasaathi.com/downloads/
वेबसाइट: parikshasaathi.com (हिंदी + English में 248 पाठ, रोज़ का करंट अफेयर्स, परीक्षा नोटिस)
ऐप: Pariksha Saathi — Free, Offline, SSC/Bank की पूरी तैयारी। लेखक/संपादक: Mahesh Srivastava, Founder.